



'हम सरकार के वरिष्ठ पार्टनर हैं'

भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव (2025) के पहले यह सत्य स्थापित कर देना चाहती है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। जद(यू) के प्रवक्ता पद से की सी. सी. तांगी के हटना या कहें कि स्वेच्छा से हटने की मुश्ख्यमें कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। इसमें से एक है बिहार के नए मुख्य सचिवके पद पर कोयला सचिव अमृतलाल मंगी की नियुक्ति की उम्मीदें थी कि, वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यात अमृत को नीतीश का रखी तांगी था, को मुख्य सचिव बनाया जाएगा पर जब वह नहीं हुआ तो अमृत निजी कारों से एक महीने की छुट्टी पर घर जाएगा।

समझा जाता है कि एक छुट्टी दिन पहले, एफसीसीएस्टर डायरेक्टर (ई.डी.) के अधिकारियों ने उन्हें बुलाया था तथा सड़क-निर्माण एवं अन्य मामलों में हुई डॉल के सचिवत में स्थानकरण मार्गी थे, हालांकि उन मामले में एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, जिसके अन्तर्गत, आलोक राज बिहार के नये डी.जी.पी. बनाये गये हैं। कुछ वर्ष पहले, जेडी.यू. और आर.जे.डी. मिलकर राज सरकार चला रहे थे, इस पद के लिए आलोक राज के नाम पर विचार हुआ था। उस समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित इसलिये प्रश्न यह है कि जब केन्द्र रूप से भाजपा के नियुक्ति हुए हैं।

- एक-एक करके केन्द्रीय सरकार के सहयोग से मु.मंत्री नीतीश कुमार पर हावी होती जा रही भाजपा बिहार में।
- इस रणनीति का पहला संकेत था केन्द्रीय सरकार में कोल सचिव अमृत लाल मंगी को भाजपा का मु.सचिव बनाना। नीतीश कुमार अपने नजदीकी प्रत्याता अमृत को सी.एस. नियुक्त करने के लिए दबाव बना रहे थे।
- यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्याता अमृत से ई.डी. ने कुछ समय पूर्व पूछताल की थी, सड़क निर्माण के कुछ बड़े टेंडरों के बारे में।
- भाजपा की धेराबंदी का दूसरा संकेत था, आलोक राज की बिहार के नये डी.जी.पी. के रूप में नियुक्ति।
- आलोक राज को डी.जी.पी. बनाने की बात जे.डी.यू. व आर.जे.डी. गठबंधन की सरकार के दौरान भी चली थी, पर, भाजपा उनकी नजदीकी देखते हुए उन्हें डी.जी.पी. नहीं बनाया गया था।
- अब बिहार के रहने वाले, आई.आर.एस. अफसर राहुल नवीन भी ई.डी. के नये निदेशक नियुक्त हुए हैं।
- मु.मंत्री के दो करीबी अफसर, उनके सचिव दीपक कुमार व संजीव हंस से भी ई.डी. ने पूछताल की व हंस के ठिकानों पर पर तो छापा भी मारा है।

अत्यधिक निर्भर है तो फिर नीतीश कुमार शीर्ष नौकरशाहों की नियुक्ति स्वतंत्रतावार्क कंपनी नहीं कर पाए हैं। दरअसल, केन्द्र सरकार तथा भाजपा उनकी गढ़ने पर अपनी पकड़ बढ़ाती जा रही प्रतीक हो रही है। कुछ महीने पहले, ऐसी अफवाह थी कि ई.डी. ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार के बेटे से पूछताल की है। इसमें पहले, ई.डी. ने बिहार के डेकर के आई.ए.एस. अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ पूरे लताराम के साथ विधिवत छापा मारा था। उन पर आरोप था कि उन्हें अर.जे.डी. के पूर्व विधायक युलावायां बाद याद करने पर रुकावा रखा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्याता अमृत और आर.जे.डी. ने एक ग्रैंड और अमृत को नियुक्त करने के लिए दबाव बना रहे थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आलोक राज बिहार के नये डी.जी.पी. के रूप में नियुक्ति।

आलोक राज को डी.जी.पी. बनाने की बात जे.डी.यू. व आर.जे.डी. गठबंधन की सरकार के दौरान भी चली थी, पर, भाजपा उनकी नजदीकी देखते हुए उन्हें डी.जी.पी. नहीं बनाया गया था।

अब बिहार के रहने वाले, आई.आर.एस. अफसर राहुल नवीन भी ई.डी. के नये निदेशक नियुक्त हुए हैं।

मु.मंत्री के दो करीबी अफसर, उनके सचिव दीपक कुमार व संजीव हंस से भी ई.डी. ने पूछताल की व हंस के ठिकानों पर पर तो छापा भी मारा है।

इसलिये प्रश्न यह है कि जब केन्द्र

सरकार जे.डी.यू. के समर्थन पर

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

इसलिये प्रश्न यह है कि जब केन्द्र

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

पर खाली कर दी गई थी कि वे कथित

समय, उनकी उम्मीदवारी इस आधार

विचार बिन्दु

क्षमा से क्रोध को जीतो, भलाई से बुराई को जीतो, दरिद्रता को दान से जीतो और सत्य से असत्यवादी को जीतो। -महात्मा बुद्ध

'बुलडोजर न्याय' या सरकारी आतंक

बुलडोजर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग जमीन खोलने में, निर्माण कार्यों में एवं उड़ानों में किया जाता है। 2017 में जैसे योगी आदित्यवाला की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार सत्ता में आई, इसका एक अलग ही उपयोग वर्चामें अधिक रहा है। आपराधिक पृथ्वी भूमि के व्यक्तियों, माफिया, सांप्रदायिक दिसं फैलाव के आरोपी आदि के विरुद्ध, योगी आदित्यवाला के द्वारा बुलडोजर का उपयोग प्रारंभ हुआ। ऐसे तथाकथित अपराधियों के खाली, जो वे आवाहनी हों या व्यवसायिक, को कुछ भी घटों में व्यक्त कर दिया गया। इस कार्यवाही के सरकार और योगी आदित्यवाला द्वारा 'तकलीन न्याय' का नाम दिया गया। यहां तक कि इसे 'बुलडोजर न्याय' और योगी आदित्यवाला को 'बुलडोजर बाबा' के नाम से जाने लाया जाता है।

लोक सभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार की सभाओं में भाजपा समर्थक कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठ कर आने लगे। भाजपा और सुखरमीं योगी जी ने यह सोचा था कि इस कार्यवाही से उन्हें चुनाव में भारी सफलता मिलेगी। लोकन परिवर्तन इसके ठीक विपरीत आए। और भाजपा की सीटें 62 से केवल 3 रह गईं।

बुलडोजर से सरकार ने उनको को प्रियक्या को किसी भी रूप से कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसका उपयोग प्रारंभ होने के केवल जन्मदी अपराधियों जैसे विकास दुबे, मुख्यां अंसरी और अंतिक अहमद जैसे लोगों के विरुद्ध ही किया गया, जिससे इसे स्वाधारिक रूप से व्यापक जन समर्थन भी मिला।

यह उल्लेखनीय है कि निर्माण को व्यास करने के कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में जैसे योगी भाजपा शासित प्रदेश परी भी इसमें पीछे नहीं रहे। थोर-थोर, इसका उपयोग अपराधियों के साथ ही समुदाय विशेष के लोगों और राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के लिए किया जाने लाया। इसके प्रभावी शासन का एक हथियार था।

इसका उपयोग कितना अधिक प्रचलित हो गया, यह जानने के लिए केवल अंग्रेज, 2022 के कुछ उदाहण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खण्डगांव में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभान में और 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मकानों को नेस्टनावूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी जुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी।

हाल ही में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता और अपराध प्रक्रियाएँ सहिता के स्थान पर भारतीय न्याय के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही है। न्यायिक व्यवस्था का कार्य होता है कि वह किसी भी आरोपी पर अपराध सिद्ध होने के बाद उसे कानून के अनुसार निर्धारित सजा दे। इसके लिए आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध हो। इसके पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही है। अपराधियों को कार्रवाई भारतीय न्याय के पश्चात एक नोटिस भर पर चिपका दिया जाता है। और संपत्ति को दो-चार घंटे में ही सबकारी जेसीबी मशीन जाकर गिरा देती है।

इस संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। एक कट्टूपंची साधु राम गिरी महाराज द्वारा मुखलमारों के विरुद्ध एक आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध हो गया। एक दूसरे के द्वारा आपराधियों के विरुद्ध जेसे विकास दुबे, मुख्यां अंसरी और अंतिक अहमद जैसे लोगों के विरुद्ध ही किया गया, जिससे इसे स्वाधारिक रूप से व्यापक जन समर्थन भी मिला।

यह उल्लेखनीय है कि निर्माण को व्यास करने के कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में केवल जन्मदी अपराधियों के विरुद्ध ही किया गया, जिससे इसे स्वाधारिक रूप से व्यापक जन समर्थन भी मिला।

यह संदर्भ में छतपुर थाने पर प्रश्न किया गया कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व उपराधियों के विरुद्ध करने का कार्य किया गया।

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एक आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही होती है। इसके पश्चात भी एक आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में केवल जन्मदी अपराधियों के विरुद्ध ही किया गया।

यह संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खण्डगांव में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभान में मकानों को नेस्टनावूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी जुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एक आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही होती है। इसके पश्चात भी एक आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में केवल जन्मदी अपराधियों के विरुद्ध ही किया गया।

यह संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खण्डगांव में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभान में मकानों को नेस्टनावूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी जुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एक आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही होती है। इसके पश्चात भी एक आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में केवल जन्मदी अपराधियों के विरुद्ध ही किया गया।

यह संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खण्डगांव में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभान में मकानों को नेस्टनावूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी जुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एक आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही होती है। इसके पश्चात भी एक आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में केवल जन्मदी अपराधियों के विरुद्ध ही किया गया।

यह संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खण्डगांव में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभान में मकानों को नेस्टनावूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी जुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एक आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुलिस जांच होती है और फिर न्यायालय में सुनवाई के बाद ही होती है। इसके पश्चात भी एक आपराधिक व्यवस्था के अनुसार दोस्त सिद्ध होने के बाद यह कार्रवाई अधिकारीयों व्यापक जनता पार्टी शासित देशों में केवल जन्मदी अपराधियों के विरुद्ध ही किया गया।

यह संदर्भ में, हाल ही के दो उदाहरण देने उपयुक्त होंगे। 10 अप्रैल 2022 को मध्यप्रदेश के खण्डगांव में, 11 अप्रैल 2022 को गुजरात के खंभान में मकानों को नेस्टनावूद करने का कार्य किया गया।

जहांगीरपुरी में तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित आदेश के पश्चात भी एक-दो घंटे तक यह कार्रवाई चलती रही, तो न्यायालय को दोबारा आदेश जारी करना पड़ा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने भी जुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले आरोपियों के विरुद्ध

प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए पहले एक आई आर दर्ज करनी होती है, फिर पुल

